

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2671/विधि

सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण पुनः वाद सं०-88/2018 में दिनांक-12.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, समाहरणालय, सहरसा को उनके पत्रांक 275 दिनांक 14.05.2018 से प्राप्त निम्न न्यायालय के जमाबंदी अपीलवाद संख्या-02/2017 का मूल अभिलेख कुल-122 पन्ना वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यद्योपरि।

प्रतिलिपि:- रामपुकार यादव व विजेन्द्र यादव व कमल किशोर यादव, सभी पिता-स्व० बाबूजी यादव, सा०-चन्दौर, थाना+अंचल-सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

(7)


प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी,
तारीख-सहित
३

आदेश की क्रम
संख्या
किस तारीख
१

12/09/2018

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा
जमाबंदी पुनरीक्षणवाद संख्या:-88/2018
रामपुकार यादव एवं अन्य.....पुनरीक्षणकर्ता
-बनाम-
राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट
--: आदेश :-

प्रस्तुत जमाबंदी पुनरीक्षणवाद श्री रामपुकार यादव वो विजेन्द्र यादव वो कमल किशोर यादव, सभी पिता-स्व० बाबू जी यादव, सा०-चन्दौर, थाना+अंचल-सौरबाजार, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्ता, सहरसा के जमाबंदी अपीलवाद संख्या-02/2017 में दिनांक 10.11.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय समाहर्ता, सहरसा के वाद सं०-03/2014 दिनांक 28.03.2015 राज्य बनाम रामपुकार यादव एवं अन्य एवं न्यायालय अपर समाहर्ता, सहरसा के द्वारा अपीलवाद सं०-19/2014 दिनांक 06.06.2017 में पारित आदेश को न्यायोचित पाते हुए अपीलार्थी रामपुकार यादव एवं अन्य के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

वादीगणों का मूल रूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि अंदर मौजा-चन्दौर, थाना-106, थाना वो अंचल-सौरबाजार, जिला-सहरसा अंदर खाता-634, खेसरा-11266, रकवा-15 कट्ठा किस्म पोखरा का अस्तित्व कोशी विभीषिका के चलते सरजमीन पर समाप्त हो गया। उक्त एराजी "गैरमजरुआ खास" था, जो कोशी विभीषिका में मिट्टी भर जाने के कारण मालिक जमीन्दार के हक दखल में आया। मालिक जमीन्दार द्वारा दिनांक 04.03.1941 ई० को वादीगणों के पिता बाबूजी मंडल को बन्दोवस्त कर परमानगी बना

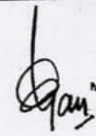
Day

भूमि पर वादीगण हकदार व दखलकार हैं। उनके पिता के द्वारा अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी हेतु आवेदन दिये जाने पर लगान निर्धारण वाद सं०-०२/१९९० दर्ज हुआ तथा नियमानुसार साक्ष्य सबूत तथा दखल कब्जा से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, सौरबाजार के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को लगान निर्धारण हेतु अनुसंशा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उक्त वाद में दिनांक ३१.०३.१९९१ को अंतिम आदेश पारित करते हुए दो रूपया एकतीस पैसा लगान निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के आधार पर बाबूजी यादव के नाम से जमाबंदी सं०-३४१ अंचल सिरिस्ता में कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया जाने लगा। वादीगणों का कहना है कि नया सर्वे कार्यवाही में सर्वे अमला के भूल व गलती से वादी के पिता के नाम बन्दोवस्ती से प्राप्त भूमि के अंश रकवा का खाता रकवा-१० डी० अनावार बिहार सरकार दर्ज हो गया, जिसके विरुद्ध वादीगण के पिता के द्वारा धारा-१०६ बी०टी० एक्ट के प्रावधान के तहत वाद सं०-३२८१०/१९९५ दर्ज किया गया। उनके अनुसार उक्त वाद में बिहार सरकार की ओर से दिनांक २२.०५.१९९८ को हाजिरी दी गई तथा दिनांक १७.०७.१९९८ ई० को अपना जवाब दाखिल किया गया। उक्त वाद में दिनांक १६.०६.२००० को सक्षम प्राधिकार के द्वारा आदेश पारित करते हुए वादीगण के पिता बाबूजी यादव के अधिकार, स्वामित्व एवं दखल कब्जा को सम्पुष्ट किया गया, जिसके अनुसार जमाबंदी संख्या-४२२६ कायम होकर मालगुजारी रसीद अपीलार्थी के पिता के नाम प्राप्त होने लगा। वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त आदेश के विरुद्ध रिविजन वाद-०३/२०१४ न्यायालय समाहर्ता, सहरसा में अन्दर धारा-१०८ बी०टी० एक्ट के तहत काफी विलम्ब से लगभग १३ वर्ष बाद सरकार की ओर से दायर किया गया, जो विद्वान समाहर्ता के द्वारा दिनांक २८.०२.२०१५ को अस्वीकृत कर दिया गया। वादगणों का कहना है कि दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान खाता-३३१२ खेसरा-१५४०५, रकवा-६५ डी० उनके पिता-बाबूजी यादव के नाम से तरमीन हो चुका है तथा अक्षुण्ण है। उक्त स्थिति में समाहर्ता, सहरसा का तत्संबंधी आदेश दिनांक १०.११.२०१८ बिल्कुल अवैधानिक

Qan'

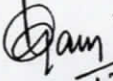
द्वारा C.W.J.C NO.-10123/2015 में पारित आदेश के अंतर्गत कि पुराना खतियान के गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास अथवा कैसर-ए-हिन्द के जमीन की बन्दोवस्ती एवं उसके सापेक्ष जमाबंदी को नाजायज नहीं कहा जा सकता एवं बिहार लैण्ड म्यूटेशन एक्ट-2011 की धारा-9 के तहत उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। समुचित आदेश हेतु व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता बनती है। उक्त के आलोक में वादीगणों के द्वारा न्यायहित में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करने तथा निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

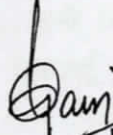
राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य में उनका वादी द्वारा किये गये दावों के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्ता, सहरसा एवं समाहर्ता, सहरसा दोनों ही न्यायालय में प्रश्नगत जमीन की जाँच की गई तथा स्थल की भी उनके द्वारा जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि पुराने सर्वे के समय से ही यह खेसरा सर्वसाधारण आम जनता के उपयोग में रहता आया है। अभी भी उसका स्वरूप जाँच के क्रम में पोखर पाया गया। उक्त जाँच में यह भी पाया गया कि दफा-106 बी0टी0 एक्ट में पारित आदेश जाली-फरेबी रिटर्न दाखिल कर नाजायज तरीके से हासिल किया गया है, जिसकी मान्यता बिहार सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई है। प्रश्नगत भूमि पुराना सर्वे से लेकर हाल सर्वे खतियान में अनावार बिहार सरकार के नाम से दर्ज हुआ तथा उसमें किस्म भी पोखर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक की जुबानी बन्दोवस्ती की कहानी गलत साबित होती है। वादीगणों के पिता को भूतपूर्व मालिक जमीन्दार के द्वारा वादगत भूमि कभी भी बन्दोवस्त नहीं किया गया तथा न आवेदक का कभी दखल कब्जा हुआ और न कोई भेस्टिंग रिटर्न मालिक जमीन्दार दाखिल किये। निम्न न्यायालय के द्वारा भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद से संलग्न कागजात के अवलोकन तथा स्थल जाँच के बाद पाया गया कि अपर समाहर्ता, सहरसा के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-03/2014 में दिनांक 28.03.2015 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा समाहर्ता, सहरसा के द्वारा अपीलवाद 19/2014 में दिनांक 06.06.2017 में पारित आदेश को न्यायोचित बताते हुए इस पुनरीक्षण वाद



उमय पदा का सुनन तथा उपयुक्त तथ्या एवं
अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के
परिशीलनोंपरान्त परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म
“गैरमजरुआ खास” तथा वर्तमान स्वरूप पोखर है, जो सर्वसाधारण
आम जनता के उपयोग में रहता आया है। वादी अपने दावा को साबित
करने में असमर्थ रहे हैं। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के
आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता
है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना
संबंधितों को दें तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित
कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।


12/9/23
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


12/9/23
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।